16-30, जून, 2023 वर्ष-1 अंक-6

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

निःशुल्कप्रति

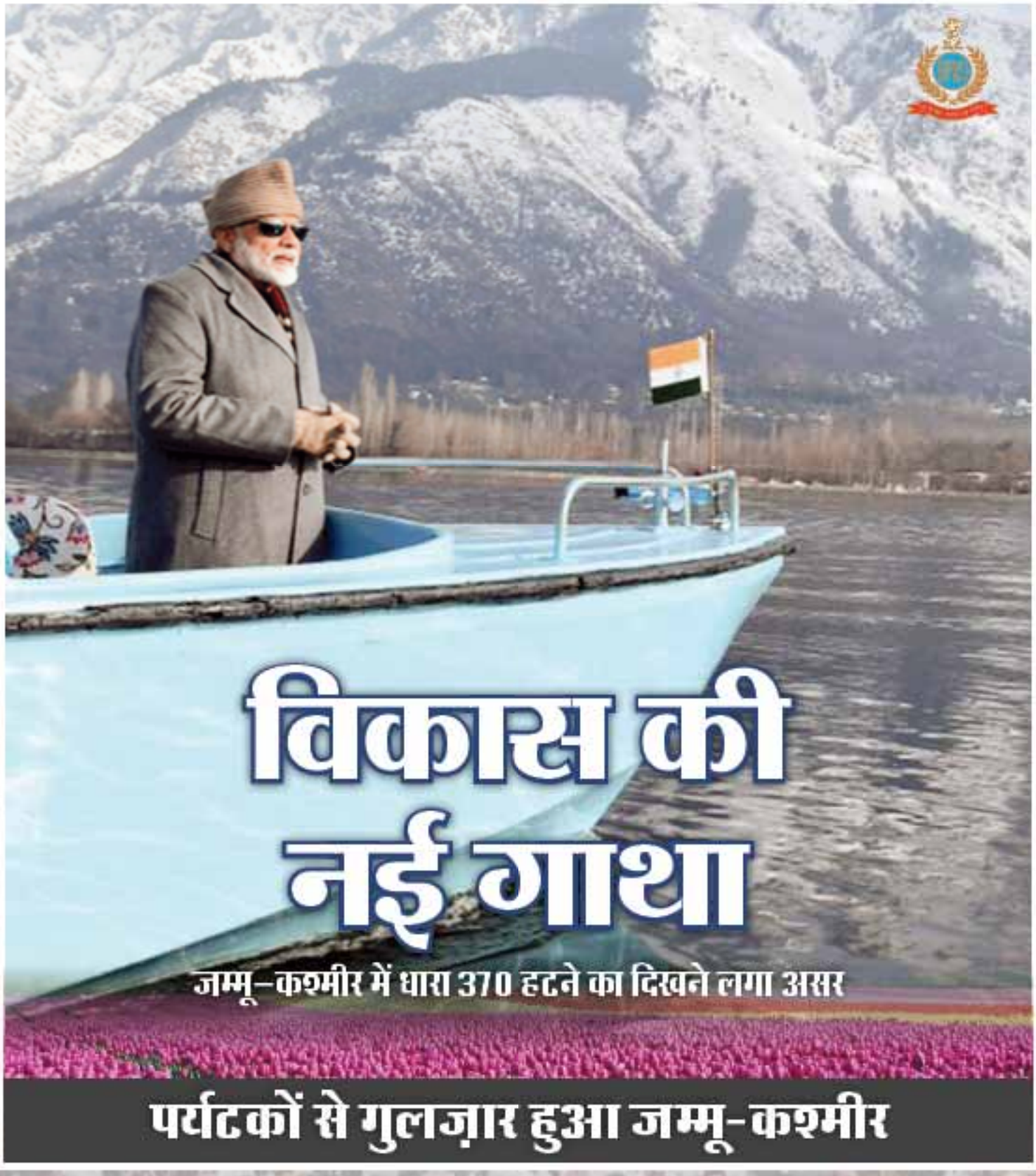

विकास की नई गाथा

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने का दिखने लगा असर

पर्यटकों से गुलज़ार हुआ जम्मू-कश्मीर

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

दुनिया में बजा भारत का डंका	14
दुनिया को दिया योग का संदेश	16
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुलभ यात्रा सरकार की प्राथमिकता	18
पहली बार मिला लद्दाख को अधिकार	20
धरातल पर उतरी परियोजनाएं	22
समावेशी सोच से लक्ष्य की प्राप्ति	24
सुरक्षा और विकास पर जोर	25
जम्मू और कश्मीर : शांति, प्रगति और विकास के नए युग का आरंभ	26

विशेष रिपोर्ट

05 विकास की नई गाथा, जम्मू–कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद...

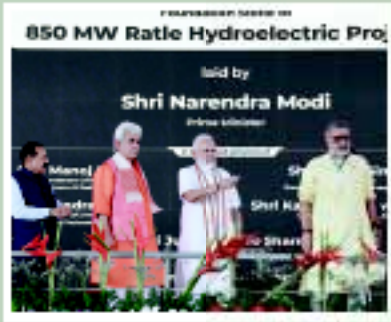

10 उपलब्धियों से दिख रहा जम्मू-कश्मीर में विकास

12 पर्यटकों से गुलज़ार हुआ जम्मू-कश्मीर

संपादक की कलम से

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने, चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल करने के लिए एक सशक्त मिशन शुरू किया है। आतंकवाद विरोधी पहल के साथ-साथ, भारत सरकार ने क्षेत्र में शांति और विकास की बहाली को प्राथमिकता दी है।

किसी देश की एकता और अखंडता समान संघीय सिद्धांत पर आधारित हो, तो लोकतंत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास जिस तरह से स्थापित हुआ है, वह सरकार के सकारात्मक प्रयासों को दर्शाता है। भारत सरकार की कुशल रणनीति और दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर ने वर्षों बाद शांति और समृद्धि का युग देखा है। यह एक नए युग का आरंभ है। यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। जहां पहले उग्रवाद, अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का बोलबाला था, वहीं अब चहुंओर शांति के साथ विकास की बयार दिख रही है।

एक ओर सरकार के उपायों ने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी है, तो दूसरी ओर इसने विभिन्न हितधारकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत और जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। इस पहल ने यहां तनाव को कम किया है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान और देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल थी। इस कदम से, संघ के कानूनों और प्रावधानों के विस्तार के साथ, आर्थिक विकास और प्रशासन बेहतर हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सक्रिय उपस्थिति और एकीकृत प्रयासों ने जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने, चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल करने के लिए एक सशक्त मिशन शुरू किया है। आतंकवाद विरोधी पहल के साथ-साथ, भारत सरकार ने क्षेत्र में शांति और विकास की बहाली को प्राथमिकता दी है। कट्टरपंथ और असंतोष के मूल कारणों को पहचान कर सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान दिया है तथा स्थानीय लोगों को त्रिस्तरीय जनतंत्र प्रणाली से जोड़ा है।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की अपार क्षमता को पहचाना है। पर्यटन से यह क्षेत्र गुलजार होगा, तो व्यवसाय और विकास के रास्ते खुद-ब-खुद चलने लगेगा। इस ओर सरकार ने बेहतरीन कदम उठाया और कश्मीर घाटी में जी20 के पर्यटन समूह की तीन दिवसीय बैठक का सफल आयोजन किया। यह एक ऐतिहासिक और साहसिक पहल है। जम्मू-कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया ने देखा और समझा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। होटल, रिसॉर्ट और अन्य मनोरंजक सुविधाओं जैसी बुनियादी परियोजनाओं का विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे पर्यटकों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो रहा है। क्षेत्र में राजमार्गों और सुरंगों के निर्माण ने परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर इसे देश के अन्य भागों से जुड़ने में सुगमता प्रदान की है। प्रगति और विकास के नए रास्ते खोले हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

'सजग भारत' का यह संस्करण विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर सहित लद्दाख में हो रहे विकास पर आधारित है। हाल के वर्षों में, सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यहां विकास को नई गति दी है। परिवर्तन अब दिख रहा है।

'सजग भारत' का यह छठा अंक आपके सामने है। हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों की प्रतीक्षा करेंगे। आप अपने सुझाव हमें dg@bprd.nic.in पर भेज सकते हैं।

जय हिंद

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

कई वर्षों के बाद हुए 'वितस्ता-द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर' से देशभर के लोगों को न सिर्फ राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिला है, बल्कि यह कार्यक्रम देशवासियों को भी एक सूत्र में पिरोने का शानदार प्रयास है।

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जम्मू-कश्मीर देश के शौर्य वीरों के अदम्य साहस व वीरता की कर्मभूमि रही है। ऐसे ही वीरों के पराक्रम को चिरजीवी बनाने के लिए श्रीनगर के प्रताप पार्क में 'बलिदान स्तंभ' का शिलान्यास किया। यह स्तंभ बलिदानियों की स्मृति को अमर कर युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देगा।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बाबा बर्फानी के पावन दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा आरंभ हुई है। यह यात्रा देश की महान सनातन संस्कृति को प्रदर्शित करती है। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा सभी श्रद्धालुओं और भक्तों पर बनी रहे।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

Led by the various reforms & significant far-sighted economic decisions, #NewIndia, under the visionary leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji is on its way to becoming a $5 trillion economy by 2024-25.

- Sh. Nisith Pramanik, Minister of State (Ministry of Home Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports)

गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई। गीता प्रेस ने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले कई दशकों से सराहनीय सहयोग किया है। गीता प्रेस परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

-श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू में CFSL, साम्बा का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया।

-केंद्रीय गृह मंत्रालय

विकास की नई गाथा

जम्मू–कश्मीर में धारा 370 हटने का दिखने लगा असर

- न गूंजती हैं गोलियां न होते हैं धमाके, प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ जम्मू और कश्मीर
- लद्दाख में भी विकास के नए युग की हुई शुरुआत

» ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैं और दायित्व भी समान हैं। जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसले ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। साल 2019 में जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। धारा 370 हटने के बाद आज जम्मू–कश्मीर के हालात भी पूरी तरह से बदल गए हैं। विकास के नए रास्ते खुल गए, लोगों के लिए रोजगार के साधन बढ़ गए, सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित होने लगे। धरती के स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी घूमने जाने वाले पर्यटकों का उत्साह भी बढ़ गया। आतंकवाद में जहां कमी आई वहीं लोगों की जीवन शैली भी बदल

गई। जिस कश्मीर के नाम पर पहले लोगों को गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों की गूंज सुनाई पड़ती थी, उस कश्मीर में आज सुख–शांति नजर आ रही है। न अब आतंकी घटनाएं घटित होती हैं और न ही पत्थरबाजी होती है। पहले औसतन हर साल के 100 दिन हड़ताल के होते थे। अब हड़ताल और पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। पहले महीनों–महीनों स्कूल, कालेज बंद रहते थे। इस परंपरा को भी पूरी तरह से दफन कर दिया गया है। अब बाजार बंद नहीं होते। यातायात के साधन की व्यवस्था में रुकावट नहीं आती। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, सरकार के प्रति आम जनता के भरोसे ने इसे संभव किया। घाटी छोड़कर जाने वाले कश्मीरी पंडितों की भी घर वापसी हो रही है। जिन हाथों में पहले पत्थर थमाया जाता था, वो हाथ अब कलम और की–पैड पर विकास की इबारत लिख रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस लगातार गश्त पर रहती है। जिन सुरक्षा बलों को लेकर घाटी में जनता को बरगलाया जाता रहा, उनके प्रति अब असीम भरोसा दिख रहा है। पत्थरबाजों, अलगाववादियों और आतंक के पैरोकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। नियंत्रण रेखा के उस पार बैठे आतंकवादी संचालकों के नापाक मंसूबों को भी नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बल कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के बाद अब यहां न दो निशान हैं और न ही दो विधान। जम्मू और कश्मीर के 205 कानून निरस्त हो चुके हैं। बीते तीन वर्ष में 890 केंद्रीय कानून जम्मू–कश्मीर में लागू हो गए हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से यहां के लोगों को अपने गांव के विकास का खाका खुद खींचने का अधिकार मिल गया है। विधानसभा हलकों क्षेत्र 83 से बढ़कर 90 हो गए हैं। कश्मीर और जम्मू संभाग के बीच सत्ता संतुलन साधा गया है। परिसीमन में जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ गई हैं। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। लालचौक से लेकर एलओसी तक तिरंगा लहरा रहा है। दस हाईवे के साथ एलओसी से एलएसी तक सड़कों का जाल बिछ गया है। वादी में बॉलीवुड लौट आया है। देश के सबसे बड़े सेब उत्पादक प्रदेश जम्मू–

सुरक्षा स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार

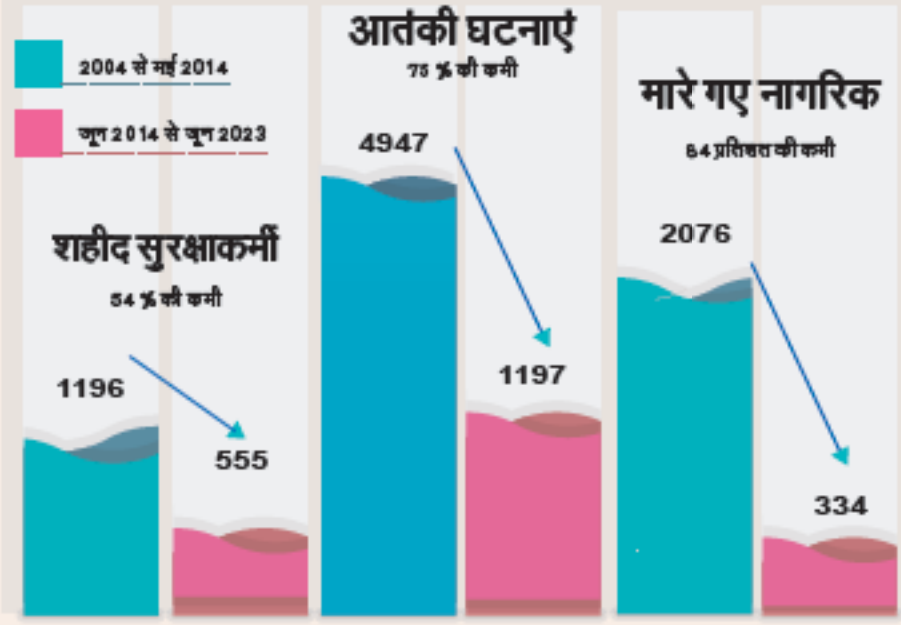

पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था - एक्सेप्ट जे एंड के। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने यहां नए उद्योगों के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है।

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नौ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास, केंद्रीय गृह मंत्रालय की कुशलता, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहित स्थानीय पुलिस की तत्परता से जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है। वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 एवं 35ए के हटाने के साथ इस क्षेत्र को पूरे देश के साथ एकाकार कर दिया। हाल ही में श्रीनगर में हुए जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन ने सरकार के निर्णय और जनता के जज्बे को सलाम किया है। अब पूरे विश्व में जम्मू-कश्मीर में सुधरे हुए हालात का संदेश पहुंचा है। स्थानीय लोग जहां अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहीं स्थानीय स्तर पर मिल रहे रोजगार से युवा भी लाभान्वित हो रहे हैं।

कश्मीर का केसर, ड्राई फ्रूट और बासमती विदेशों में महक रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर में विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। एक तरफ आतंकवाद और पड़ोसी देशों के नापाक मंसूबों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था तो दूसरी तरफ धारा 370 भी जम्मू-कश्मीर के विकास में एक बड़ी बाधा पैदा कर रही थी। धारा 370 को खत्म करने के लिए पांच साल का इंतजार करना पड़ा। 2019 में धारा 370 हटने के बाद विकास की गाड़ी आगे बढ़ गई और पूरी घाटी का परिदृश्य बदल गया है। संसद के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को एक शासन और एक विधान के दायरे में लाया गया है।

सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने के तीन साल बाद गृह मंत्रालय द्वारा दर्ज किए गए 2016-2018 और 2019-2021 के आंकड़ों के बीच तुलना की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। गौर करने योग्य यह भी है कि सरकार की तत्परता

से लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को पास कराया गया। इसके बाद अब मौजूदा जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है।

आज इस सच को हर कोई स्वीकारता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में भारत को दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम पॉलिसी, 2021 में फिल्म के लिए नई पॉलिसी, टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की पॉलिसी आदि बनाई है। इसके कारण जम्मू-कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है और पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही

आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा

अंत्योदय के मूलमंत्र और सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की भावना के प्रति समर्पित केंद्र सरकार ने दशकों तक उपेक्षित जम्मू-कश्मीर में विकास को नई रफ्तार दी है। भारत सरकार की किसी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार यह होगा कि औद्योगिक विकास को जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर तक ले जाएगी। इसके लिए नई केंद्रीय योजना के तहत अगले 15 वर्ष के लिए ₹ 28400 करोड़ की प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए ₹ 28400 करोड़ की नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के तहत ₹ 1123.84 करोड़ दिए गए। यह पहल विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रमुखता से बढ़ावा देगी। जम्मू-कश्मीर की आयात पर निर्भरता को कम करने और निर्यात की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। नई योजना को एमएसएमई की बड़ी इकाइयों व छोटी इकाइयों दोनों के लिए आकर्षक बनाया गया। जम्मू-कश्मीर के औद्योगिकीकरण का नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह योजना सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर विशेष फोकस देकर जम्मू-कश्मीर के मौजूदा औद्योगिक इकोसिस्टम में व्यापक बदलाव लाएगी। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ लगभग 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। औद्योगिकीकरण होने से कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, मछली व पशुपालन डेयरी उद्योग में रोजगार का सृजन होगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए निवेश पर जोन ए और जोन बी में क्रमशः 5 करोड़ और 7 .5 करोड़ तक के पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए ₹ 500 करोड़ तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का पूंजीगत ब्याज सब्सिडी मिलेगा। 10 वर्षों के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए वास्तविक निवेश के पात्र मूल्य का 300 प्रतिशत जीएसटी लिंक्ड प्रोत्साहन मिलेगा। नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सभी मौजूदा इकाइयों के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए एक करोड़ तक की राशि पर 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) ब्याज प्रोत्साहन मिलेगा। इससे संपूर्ण जम्मू-कश्मीर एक पसंदीदा स्थान बनकर उभरेगा और उससे औद्योगिक विकास का निर्माण होगा। इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए जम्मू-कश्मीर को सक्षम करना है।

आंकड़े दे रहे गवाही

- 2019 से जून 2022 तक जम्मू-कश्मीर में 29,806 लोगों को सार्वजनिक उद्यमों में भर्ती किया गया है।
- धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्र के 890 कानून लागू हो गए हैं।
- अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किमी सड़क ही बन पाती थी, लेकिन अब हर दिन 20.6 किमी सड़क बन रही है।
- पिछले नौ सालों में हुई आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
- साल 2022 में एक करोड़ 88 लाख पर्यटक जम्मू और कश्मीर आए।

> धारा 370 हटा कर मोदी जी ने पहाड़ी समुदाय, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को उनके आरक्षण का अधिकार दिलाया है, ये न्याय मोदी जी ही कर सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद पिछले 47 महीनों में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाओं में भी 90% की कमी आई है।
>
> -श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में रिकॉर्ड एक करोड़ 88 लाख पर्यटक जम्मू और कश्मीर आए। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, साल 1947 से 2014 तक यहां नौकरियों में भारी कमी थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने पारदर्शिता के साथ युवाओं को 28000 सरकारी नौकरियां दी, 51000 सेल्फ एंप्लॉयमेंट की यूनिट स्थापित की, मिशन यूथ के तहत 70000 युवाओं को आजीविका देने और 28400 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज देने का काम किया। अब जम्मू-कश्मीर विकास के पथ पर आगे सरपट दौड़ने को तैयार है।

23 जून को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में थे। कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के कारण विकास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारत सरकार ने किया है। पिछली सरकार के समय 10 साल में 7327 आतंकी घटनाएं हुई और 2056 नागरिक मारे गये, वहीं पिछले 9 साल में इन घटनाओं में करीब 70% की कमी आई। जब हम लेह और लद्दाख की बात करते हैं, तो यहां भी प्रधानमंत्री की विशेष नजर है। विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उन्होंने 30 जुलाई, 2022 को लेह लद्दाख में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की आधारशिला रखी। इसका लक्ष्य लेह और उसके आसपास पांच ईंधन सेल बसें चलाने का है। यह पायलट प्रोजेक्ट भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली तैनाती होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @2047' के समापन के ग्रैंड फिनाले में भाग लेते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ-साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाएं, जिनमें लेह में एनटीपीसी की ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पायलट परियोजना भी शामिल है। उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया। इससे पहले तीन फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री लेह, जम्मू एवं श्रीनगर की यात्रा के दौरान लद्दाख पहुंचे। उन्होंने वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन / शिलान्यास किया। कंपकंपा देने वाली सर्दी में वहां उपस्थित भीड़ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे हर मुश्किल को चुनौती देते हैं। आपका स्नेह मुझे कड़ी मेहनत करते रहने की प्रेरणा देता है। लद्दाख विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और कहा, 'युवा छात्र लद्दाख की आबादी के 40% हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की लंबे समय से मांग रही है। लद्दाख विश्वविद्यालय के शुभारंभ के साथ, यह मांग पूरी हो जाएगी।' यह विश्वविद्यालय लेह, कारगिल, नुब्रा, जांस्कर, द्रास और खाल्सती के डिग्री महाविद्यालयों से निर्मित एक क्लस्टर विश्वविद्यालय होगा और छात्रों की सुविधा के लिए लेह और कारगिल में प्रशासनिक कार्यालय होंगे। ■

पत्थरबाजी की घटनाओं में आई कमी

उपलब्धियों से दिख रहा जम्मू-कश्मीर में विकास

शांति एवं खुशहाली के दौर में जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बह रही है। आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा।

» ब्यूरो

बीते साल जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री ने पल्ली में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इससे पल्ली कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई। सांबा जिले की पल्ली पंचायत से देश की ग्राम सभाओं को ऑनलाइन संबोधित किया, यह कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आजादी के बाद कई साल तक कश्मीर विकास से अछूता रहा, लेकिन सरकार ने आकर बाबा साहब के सपनों को भी पूरा किया है। केंद्र की योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। पहले दिल्ली से फाइल चलती थी और कश्मीर पहुंचने में 3-4 हफ्ते लग जाते थे। अब इतने समय में कश्मीर में योजनाएं लागू हो जाती हैं। पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य, पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का केंद्र बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि, गांवों के विकास को नई ऊर्जा दे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी सरकार का बहुत जोर है।

2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में हुए विकास कार्य

सरकारी मेडिकल कॉलेज : जम्मू के कठुआ, राजौरी, डोडा और उधमपुर में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। उधमपुर को छोड़कर अन्य तीन जगहों के सरकारी मेडिकल कॉलेज कार्यात्मक हैं। उधमपुर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन चारों कॉलेजों पर ₹ 672.00 करोड़ का खर्च आएगा।

एम्स जम्मू : जम्मू के विजयपुर में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि यहां निर्माण कार्य जोरों पर है। वर्तमान में इसका प्रशासनिक परिसर जम्मू से संचालित हो रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 1253.00 करोड़ की है।

सड़कें और राजमार्ग : उधमपुर से चेनानी खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को चार लेन का बनाना, जम्मू-अखनूर राजमार्ग का चरण 2 जम्मू शहर की यातायात की समस्या से राहत देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत है ₹ 272.77 करोड़ है। रामबन जिले में बनिहाल से काजीगुंड तक 'नवयुग सुरंग' का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही आसान हो गई है। धार्मिक गांव सुधमहादेव और मानतलाई को जोड़ने के लिए चेनानी से सुधमहादेव तक दो लेन की सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 155.04 करोड़ है।

आईआईटी और आईआईएम जम्मू : आईआईटी जम्मू का एक चरण पूरा हो चुका है और शेष निर्माण कार्य पर काम जोरों से चल रहा है। वर्तमान में आईआईटी जम्मू में प्रशासनिक ब्लॉक और कक्षाएं चलायमान हैं। इस परियोजना में अनुमानित लागत ₹ 577.08 करोड़ है। इसी तरह आईआईएम जम्मू का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहां का प्रशासनिक ब्लॉक और कक्षाएं शिफ्ट व्यवस्था में कार्यात्मक हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 376.82 करोड़ है।

सीमावर्ती जिलों के लिए बंकर : सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8590 बंकरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सीमावर्ती क्षेत्र हैं- जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 369.12 करोड़ है।

एसएएसबी द्वारा श्री अमरनाथ जी आए तीर्थयात्रियों के लिए रामबन में यात्री निवास : श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने और ठहरने के लिए रामबन में यात्री निवास का निर्माण किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 46.00 करोड़ आई है। बता दें कि एक समय में इस यात्री

निवास में 3600 तीर्थयात्री ठहर सकते हैं।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर: हाल ही में जम्मू शहर में टीटीडी मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो धार्मिक पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है।

जम्मू विड़िया घर : जम्मू में जम्बू विड़िया घर का निर्माण पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 62.48 करोड़ है।

जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड : जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू शहर का सौंदर्यीकरण शुरू किया गया है। साथ ही विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं और पूरी की गई हैं, जैसे- वर्टिकल गार्डन, साइनेज, रोटरी में सुधार, साइकल ट्रैक, डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट लाइटनिंग, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिम और पार्कों का विकास, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीलेवल पार्किंग और विभिन्न परियोजनाएं।

औद्योगिक क्षेत्र : 2022-23 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र जम्मू में कुल निवेश ₹ 1416.09 करोड़ किया गया था। इससे 10506 रोजगार का सृजन हुआ, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है।

सरकारी मेडिकल कॉलेज : कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला में 2 सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इनके निर्माण में अनुमानित लागत ₹ 230.02 करोड़ आएगी। इसके अलावा हंदवाड़ा में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है।

एम्स अवंतीपोरा : अवंतीपोरा में एम्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 1828.00 करोड़ है।

निफ्ट, श्रीनगर : ओमपोरा स्थित नए परिसर से कॉलेज ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके निर्माण में अनुमानित लागत ₹ 325.36 करोड़ है।

यूनानी अस्पताल और कॉलेज, गांदरबल

कॉलेज के निर्माण में अनुमानित लागत ₹ 32.50 करोड़ आई है। इसका उद्घाटन सितंबर, 2021 में किया गया था।

स्टेडियम : पुराने बख्शी स्टेडियम को पीएमडीपी के तहत पुनर्निर्मित किया गया था। इसमें अनुमानित लागत 44 करोड़ आई थी। इस स्टेडियम का उद्घाटन 2021-22 में हुआ था। साथ ही पुराने इनडोर स्टेडियम को भी पुनर्निर्मित किया गया था। इसमें अनुमानित लागत ₹ 16 करोड़ आई थी।

नवयुग सुरंग : बनिहाल काजीगुंड रोड नवयुग सुरंग ₹ 3100 करोड़ से अधिक की लागत से बनी है। इसका उद्घाटन 2021 में हुआ। इस सुरंग से राजमार्ग के यात्रियों को 45 मिनट कम लगते हैं।

पर्यटन : ₹ 80.85 करोड़ की अनुमानित राशि से यहां नए पर्यटक सर्किट विकसित किए गए हैं। पर्यटन के लिए 75 ऑफ-बीट गंतव्यों की पहचान की गई है और उन्हें बढ़ावा दिया गया है।

डल झील: फिर से डल झील साफ-सुथरी और सुंदर हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। इसमें ₹ 85 करोड़ की अनुमानित लागत आई है। साथ ही 700 ऊर्ध्वाधर एरेटर स्थापित किए गए हैं। इसमें अनुमानित लागत ₹ 10 करोड़ आई है।

श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड : श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत श्रीनगर शहर का सौंदर्यीकरण शुरू किया गया है। इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं को लिया गया और पूरा किया गया है। ■

बन रहा है एक नया जम्मू-कश्मीर

जहां पहले अवरोध अधिक दिखता रहा, वहां अब विकास का राजपथ तैयार हो रहा है। साल 2014 से केंद्र में आई सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल किया और उसके बाद सरकारी योजनाओं का असर जम्मू के साथ ही कश्मीर की घाटियों तक देखा जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान विकास की कई सौगात इस क्षेत्र को दीं। सांबा में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक नया जम्मू-कश्मीर बन रहा है। एक जमाने में घाटी के जिन युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे आज उन्हीं युवाओं के हाथों में लैपटॉप देखकर बहुत सुकून मिलता है। पत्थर की जगह किताब लेकर पढ़े-लिखे युवा न केवल जम्मू-कश्मीर बल्कि देश के भविष्य को संवार रहे हैं। पहले इनके भविष्य पर ब्लैकटॉप लिखा हुआ था, अब ब्लैक बोर्ड पर यह अपना खुद का भविष्य लिख रहे हैं। यह परिवर्तन पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण आया है। श्री अमित शाह ने 23 जून को जम्मू में केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल), सांबा का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। जम्मू में लगभग ₹ 309 करोड़ की लागत से कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके तहत ₹ 100 करोड़ की लागत से सीएफएसएल, ₹ 157.47 करोड़ की लागत से रामबन और किश्तवाड़ में जल जीवन मिशन के तहत 41 जलापूर्ति योजनाओं, ₹ 32.46 करोड़ की लागत से डोडा में बस स्टैंड में बनाए जाने वाले बहुमंजिला पार्किंग का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ-साथ ₹ 40.86 करोड़ की लागत से बख्शी नगर में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, ₹ 17.77 करोड़ की लागत से ग्रिड स्टेशन और ₹ 25 करोड़ की लागत से डोगरा चौक से के. सी. चौक तक अपग्रेडेड सड़क का उद्घाटन भी किया गया है। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। यहां पर गोल्डन हेल्थ कार्ड वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। लगभग 97 लाख लोगों को इस गोल्डन हेल्थ कार्ड का फायदा मिल रहा है। पूरे देश भर में जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सिर्फ गरीबों को मिलती है, वहीं जम्मू-कश्मीर में सभी नागरिकों को इसके तहत 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जम्मू-कश्मीर सरकार हर रोज ₹ 2 करोड़ का भुगतान इस योजना के अंतर्गत कर रही है। ■

पर्यटकों से गुलज़ार हुआ जम्मू-कश्मीर

» ब्यूरो

धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक उग्रवाद और आतंकवाद से जूझा है। अब जम्मू-कश्मीर में स्थितियां बदली हैं। शांति और विकासात्मक पहलों वाली सरकार की बहु-आयामी रणनीति की बदौलत यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में उभरा है। जम्मू-कश्मीर के पर्यटन में आए उछाल की बात करें तो 2022 में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है। वर्ष 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर में आए थे, जबकि 2021 में यह संख्या 1.13 करोड़ थी। अकेले कश्मीर घाटी में 2022 में 26.73 लाख पर्यटक आए, जो पिछले उच्चतम दर्ज आंकड़े से दोगुने से भी अधिक है।

श्रीनगर की पहचान है डल झील। डल झील की सुंदरता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करती है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार डल झील को देश का सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र बनाना चाहती है, जिसके लिए प्रारंभिक आधार पर लगभग ₹ 85 करोड़ की योजना बनाई गई है। देश भर के बच्चे आने वाले दिनों में डल झील और टैटू ग्राउंड का दौरा करना चाहेंगे। इससे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल 'चिनाब ब्रिज' जैसे अद्वितीय बुनियादी ढांचे के साथ आगे बढ़ा है, जो फ्रांस के एफिल टॉवर से भी ऊंचा है और भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, चेनानी-नाशरी सुरंग, एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। ये जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों में से एक विभिन्न ऑफबीट गंतव्यों, सूफी/धार्मिक स्थलों, विरासत स्थलों और नए ट्रेकों की पहचान करना है। बुनियादी ढांचे के विकास और इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की पहल ने पर्यटन के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित हजरतबल तीर्थस्थल के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ₹ 42 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप, जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने वैकल्पिक आवास के विकल्प के रूप में होम स्टे

पर्यटकों की रिकॉर्ड-तोड़ संख्या

- सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर पर्यटन नीति, 2020 को अधिसूचित किया है।
- पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने से पर्यटन/आतिथ्य क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ का निजी निवेश हुआ है।
- जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (वर्ष 2022 में 1.88 करोड़ से अधिक, वर्ष 2021 में 1.13 करोड़ के मुकाबले)।
- वर्ष 2022 में 26.73 लाख पर्यटकों ने कश्मीर घाटी आए, जो वर्ष 2016 में 12.99 लाख पर्यटकों से दोगुना है।
- जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 75 ऑफबीट गंतव्यों, 75 सूफी/धार्मिक स्थलों, 75 विरासत स्थलों और 75 नए ट्रेकों की पहचान और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ने नए यहां के पर्यटन को बढ़ावा दिया है।
- हजरतबल तीर्थस्थल के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 42 करोड़ रुपये का आवंटन।

हर्षोल्लास के साथ मना खीर भवानी मेला

गांदरबल के तुलमुला स्थित माता रागन्या देवी मंदिर जिसे खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहां लोग जा नहीं पाते थे। साल 2021 के अक्टूबर महीने में जैसे ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर कश्मीरी पंडित माता रागन्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस साल 26 से 28 मई को खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ कश्मीर घाटी के स्थानीय लोगों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ट्ववीट कर शुभकामनाएं दी और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सीएपीएफ), जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को खीर भवानी मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। गांदरबल जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के आरामदायक प्रवास के लिए व्यापक और विस्तृत व्यवस्था की गई थी।

"कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित होने वाला यह खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के आध्यात्मिक जीवन में एक पवित्र स्थान रखता है। इस साल 25 हजार से भी अधिक श्रद्धालु मेले में शामिल हुए। माँ खीर भवानी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे।"

-श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। विभाग ने अब तक 1050 से अधिक होमस्टे पंजीकृत किए हैं और कई पाइपलाइन में हैं, जिससे पर्यटकों को जम्मू और कश्मीर को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही यहां के स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक लाभ में सीधे भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है। ये होमस्टे आगंतुकों के लिए एक अनूठा और गहन अनुभव प्रदान करते हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं और जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि 8 अगस्त, 2019 को देश के नाम संबोधन में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर सहित लेह क्षेत्र में पर्यटन को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। एक जमाना था, जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो, जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी, तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग यहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें।

जम्मू-कश्मीर को फिल्मिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार ने 2021 में फिल्म नीति पेश की। इस नीति ने सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से फिल्मांकन में सरलता की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा से फिल्मों, वेब श्रृंखला, वृत्तचित्रों और म्यूजिक वीडियोज के लिए कई प्रोडक्शन हाउस आकर्षित हुए हैं। इसी प्रकार हाउसबोट और शिकारा के वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए सरकार ने हाउसबोट नीति लागू की है। पंजीकृत हाउसबोट मालिकों और 'शिकारा' मालिकों को उनके रखरखाव और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विरासत प्रतीक को संरक्षित करने के लिए रियायती दरों पर लकड़ी प्रदान की जाती है।

वहीं, हम जब लद्दाख की बात करते हैं, तो लद्दाख भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में से एक है जो अपने सुंदर पहाड़ों, निराले परिदृश्यों, सुंदर ऊंचाई वाली झीलों, बिखरे हुए मठों, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। परिवहन, होटल और खानपान व्यवसायों में रोजगार के अवसर पैदा होने के कारण लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पर्यटन लद्दाख के सबसे दूरस्थ स्थानों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। पिछले कुछ दशकों में लद्दाख में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। लेह जिला विदेशी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। पैंगांग लेक समुद्र तल से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील को दुनिया की सबसे ऊंची, गहरी और लम्बी झील भी कहा जाता है। ■

दुनिया में बजा भारत का डंका

» ब्यूरो

घाटी में जी20 का सम्मेलन इस बात का प्रामाणिक आयोजन है कि कश्मीर सकारात्मक रूप से कितना बदला है। अतीत में जिस घाटी को लेकर दुनिया में संशय दिखता था, आज जी20 के कार्य समूह की बैठक ने दिखाया है कि जम्मू-कश्मीर का वर्तमान कितना बुलंद है।

हाल ही में जब जी20 के कार्य समूह की बैठक कश्मीर घाटी में हुई, तो पूरी दुनिया ने भारत सरकार के शांति और विकास के प्रयासों की सराहना की है। प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। इस दौरान आकाश से लेकर जमीन तक निगहबानी रही। डल झील में मार्कोस कमांडो का ऐसा पहरा रहा, जिनके चाहे बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने गोल्फ के एक सत्र का आनंद लिया। साथ ही डल झील के किनारे प्रसिद्ध मुगल गार्डन की सैर भी की। जी20 प्रतिनिधियों ने श्रीनगर की डल झील में प्रसिद्ध शिकारा नाव की सवारी का आनंद लिया। शिकारा बोट राइड लोगों को काफी पसंद आई। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। हरे भरे ऊंचे चिनार के पेड़ों के बीच यह प्रतिनिधि टहलते दिखे और कइयों ने तो कश्मीरी पारंपरिक लिबास में तस्वीरें भी खिचाईं।

असल में, यह बैठक इस सच को पूरी दुनिया के सामने जगजाहिर कर रही थी कि करीब 30 वर्षों तक आतंक के साए में रहने वाला जम्मू-कश्मीर का माहौल अब बदल गया है। इस बदले हुए माहौल में लोग खुश हैं और इस परिवर्तन की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 एवं 35ए हटने के बाद जम्मू और कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है। ऐसा लगता है कि कश्मीर घाटी में शांति का दशक लौट आया है। पर्यटन पर जी20 की कार्यकारी समूह की तीन दिनों तक चली बैठक के दौरान कश्मीर की खूबसूरती देश और दुनिया के सामने आई है। कश्मीर को पृथ्वी पर एक स्वर्ग माना जाता है। हमेशा से ही यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, भरपूर वन्य जीवन, उत्तम स्मारकों, मेहमान नवाज लोगों और स्थानीय हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अपने बीच देशी और विदेशी मेहमानों के होने की खुशी स्थानीय लोगों के चेहरों पर सहजता से देखी जा सकती थी। अब स्थानीय लोगों को यह भरोसा हो चला है कि एक देश में एक विधान से विकास का सुगम रास्ता खुलता है। इस बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, एमएसएमई और स्थल प्रबंधन जैसे पांच प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। असल में, ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र के परिवर्तन को गति देने और 2030 सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख आधार हैं। जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों-2030 को प्राप्त करने

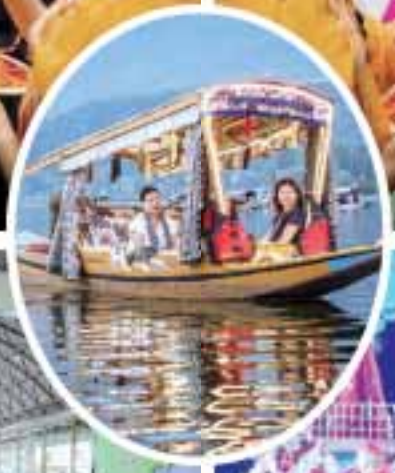

की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी का स्वागत किया। दरअसल, यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस जम्मू-कश्मीर को लेकर दुनिया भर के मंचों पर पहले आलोचनाएं और गलतबयानी होती थी, उसी कश्मीर को 17 देशों के लोगों ने भारत का अभिन्न अंग स्वीकारा है। यहां आए और अच्छी यादें लेकर गए। जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन दुनिया भर में गलतबयानी दे रहे थे, वैसे में जी20 देशों में तुर्की, चीन और सउदी अरब को छोड़कर सभी देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में जी20 देशों के सम्मेलन में पहुंचे, तो यहां के माहौल की जमकर प्रशंसा की। तीन दिनों तक विदेशी मेहमानों को कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिला। जी20 के प्रतिनिधियों ने माना कि कश्मीर की खूबसूरती और मेहमाननवाजी को देखकर वे बेहद प्रभावित हैं और यह दौरा यादगार रहेगा, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ■

विदेशी प्रतिनिधियों ने कहा, अद्भुत है कश्मीर

जिस जम्मू-कश्मीर की पहचान आतंक, विदेशी घुसपैठ और पत्थरबाजी की थी आज वहां के अमन चैन को देख विदेशी प्रतिनिधि भी अभिभूत हुए। विदेशी प्रतिनिधियों ने जहां एक तरफ जम्मू-कश्मीर की सुंदरता को सराहा तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों का प्रेम पाकर भी अभिभूत हुए।

चांग जे बाक
दक्षिण कोरिया

भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बाक ने कहा कि जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक पूरी तरह से सफल रही है। सियोल भारत की अध्यक्षता का पुरजोर समर्थन करता है और उम्मीद है कि जी20 की बैठकों को सफल बनाएगी। उन्होंने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि कश्मीर अद्भुत स्थल और यहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं।

जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में शामिल होने आए ब्राजील के प्रतिनिधि गुस्तायो ने कहा कि पर्यटन के लिहाज से यह सबसे अच्छी जगह में से एक है। स्कीइंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग आदि जैसी बहुत सारी साहसिक गतिविधियों के अलावा यहां हाउसबोट में ठहरना और शिकारा राइड अलग तरह का अनुभव है। गुस्तायो ने कहा कि वे बार-बार कश्मीर आना चाहेंगे।

गुस्तायो
ब्राजील

सिंगापुर के भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर से ज्यादा इस धरती पर कोई खूबसूरत जगह नहीं है। कश्मीर का हस्तशिल्प लाजवाब है। वोंग ने कहा कि हमने यहां आकर योग भी किया और जिन स्थलों का भ्रमण किया उसको शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे।

साइमन वोंग
सिंगापुर

दुनिया को दिया योग का संदेश

अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हुए शामिल

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून, 2023 को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, 'योग का अर्थ है– एकजुट होना। आपका एक साथ आना योग के दूसरे रूप की अभिव्यक्ति है। मुझे याद है, लगभग नौ वर्ष पहले, यहीं संयुक्त राष्ट्र में, मुझे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव देने का सम्मान मिला था। उस समय पूरी दुनिया का इस विचार के समर्थन में एक साथ खड़ा होना अविस्मरणीय था। मैंने अभी-अभी वीर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं। 2015 में, मैंने उनकी याद में संयुक्त राष्ट्र में एक नवीन स्मारक के निर्माण का आह्वान किया था। और पिछले हफ्ते, पूरी दुनिया ने इसे शीघ्र ही साकार करने के लिए भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई। सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी का योगदान करने वाले देश के रूप में, हम इस नेक कार्य में समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए सभी देशों के आभारी हैं। पिछले वर्ष, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पूरी दुनिया ने एक साथ समर्थन जताया था। मिलेट एक सुपरफूड है। वे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी उत्तम हैं और आज, पूरी दुनिया को फिर से योग के लिए एक साथ आते देखना अद्भुत है! हम योग की शक्ति का उपयोग मित्रता के सेतु, एक शांतिपूर्ण दुनिया और एक स्वच्छ, हरित और दीर्घकालिक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए करें। आइए हम सब मिलकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करें।'

इस वर्ष की थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग' है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' यानी 'एक पृथ्वी – एक परिवार – एक भविष्य'। इस कार्यक्रम में 135 से अधिक देशों के योग के प्रति उत्साहित हजारों लोगों की जबरदस्त रुचि देखी गई, जिसने एक योग सत्र में अधिकतम संख्या में देशों के लोगों द्वारा भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत के आह्वान पर 180 से अधिक देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। 2014 में रिकॉर्ड संख्या में देशों के समर्थन को याद किया, जब योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वैश्विक आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से एक वैश्विक उत्साह बनाने के लिए पेश किया गया था। अमेरिका के राजकीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हजारों भारतीय-अमेरिकी भी मौजूद थे।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के अध्यक्ष महामहिम श्री केविन मैककार्थी; सीनेट में बहुमत के नेता महामहिम श्री चार्ल्स शूमर; सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता महामहिम श्री मिच मैककोनेल और सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महामहिम श्री हकीम जेफ्रीस के निमंत्रण पर 22 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। ■

13 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने 25 जून 2023 को काहिरा की प्रेसीडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया।

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विदेश में एक और प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने 25 जून 2023 को काहिरा की प्रेसीडेंसी में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत के लोगों की ओर से राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल-सिसी ने 25 जून को अल-इत्तिहादिया पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति श्री सिसी की राजकीय यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया। साथ ही इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि मिस्र की कैबिनेट में नव गठित इंडिया यूनिट द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कारगर है। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच विशेष रूप से व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्री सिसी ने खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के लिए मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों को रेखांकित करते हुए जी-20 में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जी-20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री सिसी का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता प्रकट की। इस अवसर पर मिस्र के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मुस्तफा मैडबौली और उनकी कैबिनेट के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर देश की राजकीय यात्रा करने वाले मोदी ने अल-सीसी के साथ आमने-सामने की बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र तथा विश्व में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की समीक्षा की। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। साझा हित के कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। राष्ट्रपति अल-सीसी ने जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय अध्यक्षता में मिस्र का विश्वास व्यक्त किया, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के नकारात्मक असर को रोकने में योगदान देता है।

सबसे खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 24 जून 2023 को काहिरा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में, प्रधानमंत्री ने भारत-मिस्र संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए इस समुदाय की सराहना की। इस

कार्यक्रम में छात्रों, पेशेवरों और व्यावसायियों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय के 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। ■

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुलभ यात्रा सरकार की प्राथमिकता

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।
- श्री अमरनाथ यात्रा के सभी तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान कार्ड (आरएफआईडी) दिए गए हैं। इससे उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगता है।
- प्रत्येक अमरनाथ यात्री के लिए ₹ 5 लाख और प्रत्येक जानवर के लिए ₹ 50000 का बीमा किया गया है।
- हर तीर्थयात्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा कर रहा है।

» ब्यूरो

हर साल सावन महीने में देशवासियों को प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा की प्रतीक्षा होती है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए सुरक्षा आदि की पूरी व्यवस्था के लिए उचित दिशा-निर्देश दिया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय पुलिस बल के साथ भारतीय सेना हर तीर्थ यात्री की सुगमता के साथ व्यवस्था करती है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई है। सरकार की ये प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हो और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अमरनाथ यात्रा सुगम और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए 9 जून को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा व केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर हर संभावित बिंदु पर चर्चा की गई। बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव, सेना और केंद्र सरकार तथा जम्मू और कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

सरकार की ये प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रियों को सुगमता से दर्शन हों और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। यात्रा की सुरक्षा

के साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस तथा हेलीकाप्टर तैनात करने को भी कहा। साथ ही अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये। यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूस्खलन होने की स्थिति में मार्ग तुरंत खोलने के लिए मशीनें तैनात करने के निर्देश भी दिये।

62 दिन तक चलने वाली यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण होती है। केंद्र सरकार ने अमनाथ यात्रा को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा का माहौल प्रदान किया है, ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस यात्रा में किसी श्रद्धालु को सड़क मार्ग में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके भी यात्रा मार्ग को सीमा सड़क संगठन की तरफ से पहले ही पूरा कर लिया जाता है। इस कार्य में मार्ग पर जमी बर्फ की सफाई, मार्ग को चौड़ा करना, सभी पैदल पुलों की मरम्मत, हैंड रेलिंग, ब्रेक वॉल फिक्सिंग का निर्माण आदि सब कार्य सम्मिलित है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 49 अधिकारियों को विभिन्न यात्रा रूट पर कैंप निदेशक और अतिरिक्त कैंप निदेशक के तौर पर तैनात किया गया है।

इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह रही कि श्री अमरनाथ यात्रा के सभी तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान कार्ड (आरएफआईडी) दिए जाएंगे, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके तहत प्रत्येक अमरनाथ यात्री के लिए ₹ 5 लाख और प्रत्येक जानवर के लिए ₹ 50,000 का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर टेंट सिटी, वाई-फाई हॉटस्पॉट और उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बाबा बर्फानी के ऑनलाइन-लाइव दर्शन, पवित्र अमरनाथ गुफा में सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण और आधार शिविर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार की ओर से हर वर्ष अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, शांत एवं विश्वासपूर्ण वातावरण में कराने की पूरी तैयारी की जाती है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर राज्य प्रशासन अभेद्य सुरक्षा रणनीति तैयार करता है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की महती भूमिका होती है। इस साल यात्रियों की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां दूसरे राज्यों से बुलाई गई हैं। श्रद्धालुओं के जत्थे और आधार शिविरों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) व स्थानीय पुलिस संभालेगी। यात्रा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास रहेगी।

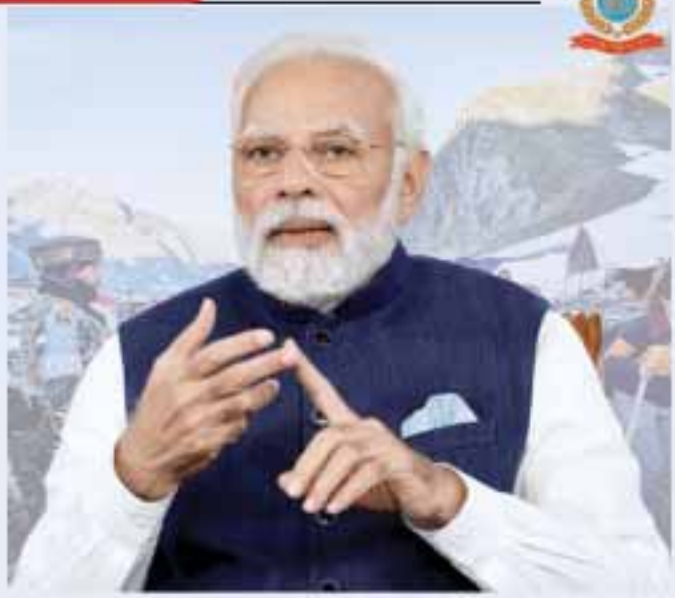

> श्री अमरनाथ जी की यात्रा हमारी विरासत का एक दिव्य और भव्य स्वरूप है। मेरी कामना है कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से सभी श्रद्धालुओं के जीवन में नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हो, साथ ही अमृतकाल में हमारा देश संकल्प से सिद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़े।
>
> -श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सीआरपीएफ का एक दस्ता जम्मू से पहलगाम व बालटाल आधार शिविर तक श्रद्धालुओं के वाहनों के साथ चलेगा। जत्थे के बीच में भी सीआरपीएफ के जवानों का एक वाहन मौजूद रहेगा। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर ऊधमपुर से आगे काजीगुंड तक सेना के जवान तैनात रहेंगे। वह आसपास के पहाड़ों और जंगलों के अलावा हाईवे पर सभी प्रमुख बाजारों व गांवों में पुलिस व सीआरपीएफ के साथ तलाशी अभियान चलाएंगे। ■

अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं में दिख रहा खासा उत्साह

शिवम देसाई

रवि दीक्षित

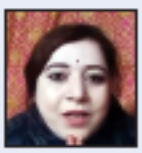

आरती शर्मा

अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने सुरक्षा और सुलभ यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं वहीं श्रद्धालु भी व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। गुजरात से आए शिवम देसाई ने बताया कि यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। चाहे वे सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हो या फिर खान-पान की व्यवस्था देखने वाले कर्मचारी। गुजरात के रहने वाले राहुल पटेल ने बताया कि खराब मौसम में भी यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ताकि किसी यात्री को दिक्कत न हो।

गोरखपुर के रहने वाले रवि दीक्षित का कहना है कि प्रतिकूल मौसम में भी जगह-जगह पर सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। दिल्ली की रहने वाली आरती शर्मा ने कहा कि जम्मू से लेकर अमरनाथ यात्रा के हर कदम पर हमें सीआरपीएफ की ओर से पूरी सुविधा और सुरक्षा मिली हुई है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। प्रत्येक यात्री बीएसएफ और सीआरपीएफ की प्रशंसा कर रहा है।

हरियाणा की रहने वाली सोनिका ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी साथी सुरक्षा के साथ सफाई और रहने की व्यवस्था पर पूरा फोकस कर रहे हैं। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरा ख्याल रख रही है।

वहीं सोनिया का कहना था कि जम्मू-कश्मीर के बारे में जो सुना था वैसा कुछ नहीं है। लोगों को अब सरकार पर भरोसा हो गया है कि यात्रा सुरक्षित और सुलभ होगी। लोग पहले से अधिक अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं। कई यात्रियों ने कहा कि सीआरपीएफ के हर जवान और प्रत्येक अधिकारी यात्रियों के हर कदम पर उनके साथ खड़े होते हैं।

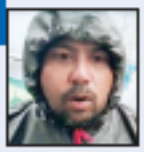

राहुल पटेल

सोनिका

सोनिया

पहली बार मिला लद्दाख को अधिकार

» ब्यूरो

काम करने का मन हो तो, बाधाओं की परवाह नहीं की जाती और परिणाम सार्थक मिलते हैं। यह बात लद्दाख में लागू होती है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। सरकार ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला किया, इस पर ₹ 750 करोड़ की लागत आयेगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर मिल सकेगा। स्थानीय छात्रों को उच्च और बेहतर शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की। इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दोनों को अलग केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की तरफ से यह कहा गया कि काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिले, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करना लद्दाख क्षेत्र के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों को देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद 370 को हटाना उसी दिशा में एक कदम है। लद्दाख की स्थिति में बदलाव और बढ़ाए गए बजट से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया है। सरकार के लिए लद्दाख में विकास करना पहली प्राथमिकता है। सरकार ने लद्दाख को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2025 तक पूरी होने वाली 4.1 किमी लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण के लिए ₹ 1,681.51 करोड़ को मंजूरी दी है। लद्दाख के सबसे पिछड़े क्षेत्र जांस्कर की तुंगनाक घाटी के निवासियों ने इस फैसले के लिए सरकार का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। दरअसल, केंद्र के सुरंग बनाने की मंजूरी देने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2019 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख का पहला विंटर-ग्रेड डीजल आउटलेट का उद्घाटन किया था। इस विंटर-ग्रेड डीजल आउटलेट की खासियत है कि यह बर्फीली सर्दी में भी ईंधन को जमने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ग्रेड डीजल ईंधन में तरलता की कमी के कारण लोगों को होने वाली समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। यह विंटर-ग्रेड डीजल न केवल अत्यधिक ठंड में पर्यटन सीजन के दौरान यात्रा और परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों की पर्यटन और आपूर्ति जरूरतों को बढ़ावा देने और समग्र रूप से मदद करने में भी मदद करेगा। खास बात है कि पहली बार पानीपत रिफाइनरी द्वारा उत्पादित शीतकालीन ग्रेड डीजल का प्रवाह बिंदु -33 डिग्री सेल्सियस है और डीजल के सामान्य ग्रेड के विपरीत क्षेत्र के अत्यधिक सर्दियों के मौसम में भी इसकी तरलता क्षमता कम नहीं होती है, जिसका उपयोग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार इस विंटर-ग्रेड डीजल आउटलेट के लॉन्च से चरम मौसम की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

सबसे अच्छी बात है कि स्थानीय कराधान के नए शुरू किए गए प्रावधानों से उनके वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि होगी। ₹ 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 7500 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में समृद्धि आएगी। 9 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के अलावा, ₹ 50,000 करोड़ की लागत से 7500 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना 4 वर्षों में पूरी हो जाएगी। इससे न केवल लद्दाख क्षेत्र में विकास होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

बिजली के लिए श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, लेह और कारगिल के लिए 14 सौर परियोजनाएं, लद्दाख विश्वविद्यालय, 2 नए डिग्री कॉलेज, 5 नए पर्यटक सर्किट और ट्रैक सहित पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए रियायती हेलीकॉप्टर सेवा और जिला अस्पताल का उन्नयन और लद्दाख, लेह और कारगिल के लोगों को अब समान अधिकार प्राप्त हैं और ये देश के विकास में समान भागीदार होंगे। ■

> अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। यहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल हो रहा है और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बन रहे हैं। लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए बेहतर संस्थान खुल रहे हैं। लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।
>
> **श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2019 में लद्दाख का पहला विंटर-ग्रेड डीजल आउटलेट का उद्घाटन किया।
- 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग के निर्माण के लिए ₹ 1,681.51 करोड़ की मिली मंजूरी।
- 9 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के अलावा, ₹ 50,000 करोड़ की लागत से 7500 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना 4 वर्षों में हो जाएगी पूरी ।
- लद्दाख ने आधार वर्ष 2020-21 में एटी एंड सी घाटे को 48.17% से धीरे-धीरे कम करके 2024-25 तक 27.85% करने की परिकल्पना की है।

पेंसिल वाला गांव

» ब्यूरो

कश्मीर के पुलवामा का नाम आते ही अब 14 फरवरी, 2019 की दहशतगर्दी नहीं, नए भारत की तस्वीर उभरेगी। पुलवामा के उक्खू गांव को केंद्र सरकार की पहल पर 'पेंसिल वाला गांव' का टैग दिया जा रहा है। इसलिए अब पुलवामा को देश के बच्चों की शिक्षा में अक्षर ज्ञान वाली पेंसिल के लिए जाना जाएगा। देश में जिन हाथों ने पेंसिल थामी है या थामी होगी, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि यह पेंसिल कहां से बनकर उनके हाथों तक पहुंची है। लेकिन यह जानकार सुखद अनुभूति होगी कि आपके हाथों में आने वाली 90 फीसदी पेंसिल भी उसी पुलवामा से होते हुए पहुंचती है। पुलवामा जिले का उक्खू गांव अब मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास की नई रफ्तार भरने को तैयार है। केंद्र सरकार भी जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने में जुटी हुई है। पुलवामा का उक्खू गांव अभी तक सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल स्लेट (लकड़ी की पट्टी) देशभर में भेजता था, लेकिन अब बदलते कश्मीर में यहीं से पूरी पेंसिल तैयार करके पूरे देश में भेजी जाएगी। यह गांव अब स्पेशल जोन के रूप में विकसित होगा। इस गांव में 400 से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। बीते साल इस गांव में पेंसिल से ₹ 107 करोड़ का राजस्व मिला है। इसी तरह अनंतनाग जिले के गांवों में भी पेंसिल के खांके बनाए जाते हैं। ऐसे में उक्खू को पेंसिल वाला गांव का टैग मिलने से लोगों को सब्सिडी मिलेगी और वे उद्योग जगत में अपना योगदान दे सकेंगे। इससे कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। 1960 के दशक में यहां पेंसिल का उत्पादन करने के लिए देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इससे जंगलों और पर्यावरण को नुकसान होता था। इसलिए बाद में देवदार की जगह पापुलर के पेड़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पेंसिल निर्माण के लिए सिर्फ 10 फीसदी ही लकड़ी यहां केरल से मंगवाई जाती है, जबकि बाकी लकड़ी की आपूर्ति पुलवामा से ही हो जाती है। लकड़ी की कारीगरी के साथ- साथ क्रिकेट बैट के लिए भी दुनियाभर में मशहूर कश्मीर को जरूरत है नया बाजार उपलब्ध कराने की। ऐसे में केंद्र सरकार की यह पहल हस्तशिल्प को प्रोत्साहन के साथ वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूती देगी। कच्चे माल की जगह अब पूरी पेंसिल पुलवामा से बनकर देश के हर हाथ में होगी। ■

क्रिकेट में भी आगे हैं जम्मू-कश्मीर के युवा क्रिकेटर

विकास की लहर जम्मू-कश्मीर में भी बह रही है। इसकी छोटी-सी बानगी है क्रिकेट। जिससे पूरी दुनिया ने 31 मार्च से आरंभ हुए आईपीएल में देखा। पहली बार जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा रहे। इनमें पांच खिलाड़ी विभिन्न टीमों का हिस्सा रहे, जबकि छह खिलाड़ी बतौर नेट गेंदबाज विभिन्न टीमों के साथ जुड़े रहे। नेट गेंदबाज के चुने गए गेंदबाजों में मुंबई इंडिया में वसीम बशीर, लखनऊ सुपर जयांट्स में आदि मुश्ताक और मुजतबा युसूफ, सीएसके के साथ उमर नजीर और कोलकत्ता नाइट राइडर में समीउल्लाह डार शामिल हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ज्यादा संख्या में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। नेट गेंदबाजी के चुने गए गेंदबाजों में ऐसे भी खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी तक जम्मू-कश्मीर के लिए खेला नहीं है। इसे विकास ही कहेंगे। प्रतिभाएं यहां छिपी हैं, बस आईपीएल जैसे अवसर मिले तो प्रतिभाएं निखरती हैं और दुनिया देखती है और तो और जम्मू में पहली बार लोग बड़ी स्क्रीन में लाइव सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला देख सकेंगे। कश्मीर का क्रिकेट बैट उद्योग 102 साल पुराना है। वहीं, अब कश्मीर का क्रिकेट बैट उद्योग फेमस इंग्लिश विलो के निर्माताओं को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक क्रिकेट खेलने वाले देशों ने अब कश्मीर विलो से बने बैट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। टी20 विश्व कप में कुछ टीमों द्वारा उपयोग किए जाने के बाद अब कश्मीर के बल्लेबाजों ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के क्वालीफाइंग राउंड में पदार्पण किया है। बैट निर्माण के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कश्मीर विलो से बने बैट का उपयोग 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप में किया जाएगा।

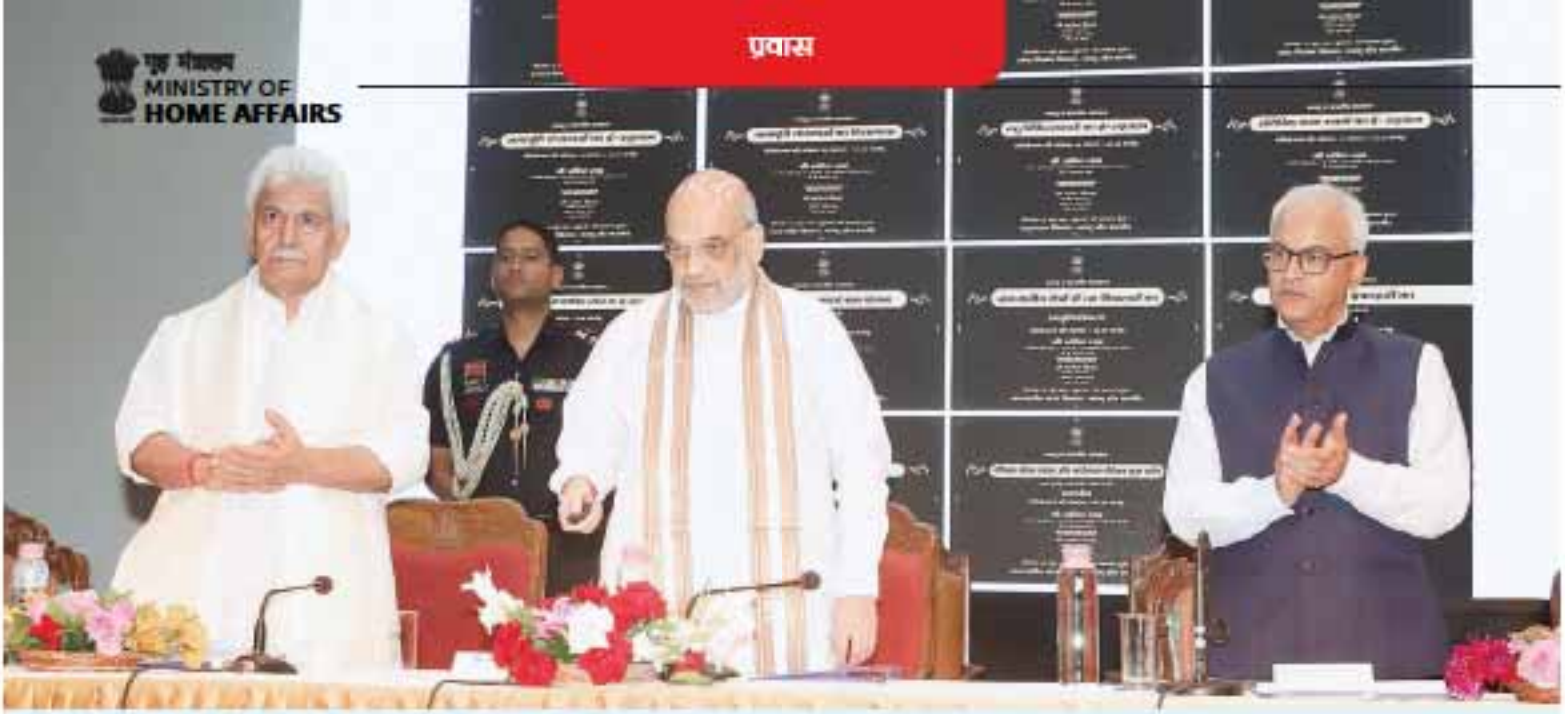

धरातल पर उतरी परियोजनाएं

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की

» ब्यूरो

जब समस्याओं का बेहतर समाधान हो, तो समाज और राज्य का विकास किस द्रुत गति से होता है, इसे बेहतर तरीके से देखना और समझना है, तो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर बेहतर उदाहरण है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशन में कानून व्यवस्था का बेहतर अनुपालन और स्थानीय प्रशासन के तालमेल से इस प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सरकार की ओर से लगातार नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

23 जून को केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री श्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने श्रीनगर में लगभग ₹ 586 करोड़ की लागत वाली 84 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा में आज एक नया मुकाम हासिल हुआ है। आज यहां लगभग ₹ 586 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिनसे लगभग 22 लाख लोगों को किसी ना किसी प्रकार से फायदा होगा और उनकी रोजमर्रा की ज़िन्दगी आसान बनेगी। आधुनिक शिक्षा से घाटी के बच्चे महरूम ना हों, इसके लिए 100 स्कूलों का आधुनिकीकरण हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे जम्मू और कश्मीर में किसी भी नागरिक के ₹ 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा मोदी सरकार उठा रही है। देशभर में ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए लागू हुई है और जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ सेहत को भी जोड़ कर यहां के हर नागरिक को कवर किया है। जम्मू और कश्मीर में छोटी-छोटी कई योजनाओं से लाखों नागरिकों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां के 12 लाख 45 हजार किसानों के बैंक खातों में ₹ 6 हजार प्रति वर्ष भेजते हैं, जिससे किसानों को ऋण लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तीन सालों में ₹ 100 करोड़ जम्मू और कश्मीर के किसानों को मिले हैं। जल जीवन मिशन के तहत 11 लाख 96 हजार परिवारों को घर में नल से फ्लोराइड-रहित जल देने का काम पूरा हो गया है। 13 लाख 80 हजार परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी शौचालय नहीं था, इन घरों में शौचालय बनाने का काम 5 साल में पूरा हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 65 लाख 91 हजार लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री देने का काम सरकार कर रही है। लगभग 1.86 लाख लोगों को घर देने का काम सरकार पूरा कर चुकी है। डीबीटी स्कीम के तहत 4 सालों में ₹ 23 हजार करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई एम्स, आईआईएम, आईआईटी और आईआईआईटी जम्मू और कश्मीर को दिए हैं। डल झील को हम देश का सबसे आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए अभी प्राथमिक रूप से लगभग ₹ 85 करोड़ की योजना बनी है। कई नए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हुए हैं। ■

पूरे विश्व को कराया कश्मीर दर्शन

वितस्ता महोत्सव पूरे विश्व को कश्मीर का दर्शन कराने वाला एक महोत्सव है। इसका उद्देश्य पूरे देश को कश्मीर की महान सांस्कृतिक विरासत, विविधता और विशिष्टता से परिचित कराना है।

» ब्यूरो

वितस्ता महोत्सव कश्मीर की विशेषता को पूरे भारत और विश्व में पहुंचाने वाला राजदूत है। पिछले 25 वर्षों में कश्मीर में वितस्ता महोत्सव आयोजित होने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस महोत्सव का नाम झेलम नदी के मूल संस्कृत नाम से लिया गया है। इसमें कश्मीर से 1,900 और भारत के अन्य हिस्सों से 150 कलाकारों ने भाग लिया। यह महोत्सव देश की विविध संस्कृतियों का संगम होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वितस्ता महोत्सव के माध्यम से ही कश्मीर को सबको समाहित करने वाली और एक बहुत बड़े मन वाली विचारधारा और संस्कृति बताया है। उनका कहना है कि यहीं संगीत और ज्ञान ने ऊंचाइयों को छुआ इसीलिए आदिशंकर ने इसे शारदा क्षेत्र कहा और यहां शारदा पीठ की स्थापना की। कश्मीर में आयोजित वितस्ता महोत्सव में कश्मीर के लगभग 1900 कलाकार और देशभर के लगभग डेढ़ सौ कलाकारों ने यहां अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और एक्सचेंज किया। देश को एक करना है तो कला, संस्कृति और देश का इतिहास ही कर सकता है, वितस्ता महोत्सव इसका एक अनूठा आयोजन है जहां देशभर के व्यंजन का स्वाद लोगों ने लिया और देशभर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। श्री अमित शाह स्वीकारते हैं कि जब तक हमारी संस्कृति और कला को देश को जोड़ने के काम में हम नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इस अभूतपूर्व शक्ति को देश के उपयोग में नहीं लगा सकेंगे। हमारी अलग संस्कृतियां, भाषाएं, वेशभूषाएं और खानपान होते हुए भी हम सब भारतीय हैं, यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं है जितनी हमारे भारत में है। ■

जवानों की वीरता को सलाम, शहीदों के परिजनों को सम्मान

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है। इसके पीछे प्रमुख कारण सुरक्षाकर्मियों की जहां मुस्तैदी है वहीं केंद्र सरकार का गंभीरता पूर्वक ध्यान देना भी है। जिसमें सुरक्षाकर्मी की हर सुविधाओं का केंद्र सरकार ध्यान रख रही है। इतना ही नहीं अगर कोई जवान शहीद हुआ तो उसके परिजनों को तत्काल हर सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। सरकार ने आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए कई उपाय किए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय अभियान, जमीनी कार्यकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी, प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई, रात्रि गश्त तेज करना, उचित तैनाती के माध्यम से गहन सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बैठकें, टेरर फंडिंग आदि के मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई से जम्मू-कश्मीर में शांति आई है।

सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच उत्साह जगे इसके लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। यह स्तंभ देश के युवाओं को जहां देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा वहीं शहीद हुए जवानों के परिजनों को संबल भी प्रदान करेगा। श्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ के शिलान्यास के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर देश के शौर्य वीरों के अदम्य साहस व वीरता की कर्मभूमि रही है। ऐसे ही वीरों के पराक्रम को चिरंजीवी बनाने के लिए श्रीनगर के प्रताप पार्क में 'बलिदान स्तंभ' का शिलान्यास किया। यह स्तंभ बलिदानियों की स्मृति को अमर कर युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देगा। इस दौरान श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर नियुक्ति पत्र वितरित किये। श्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के असंख्य जवान, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर और वहाँ के लोग शांति के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। बीते नौ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी मजबूत करने का काम किया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में आतंक की घटनाओं में जहां कमी आई वहीं इधर पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रशासित प्रदेश सतत स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आतंकी घटनाओं में करीब 54 फीसदी, सुरक्षा बलों के जवानों की मौत के मामले में 84 फीसदी और आतंकी भर्ती के मामलों में 22 प्रतिशत की कमी आई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों की अब तक की सबसे कम संख्या पर संतोष व्यक्त किया। सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शांति को स्थायी बनाने के लिए शेष आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के प्रयासों में तेजी लाएं। ■

समावेशी सोच से लक्ष्य की प्राप्ति

» ब्यूरो

भारत सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में युवाओं को एक ओर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, दूसरी ओर देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व आने वाले इन युवाओं पर होगा। लड़कों के साथ ही काफी संख्या में लड़कियों ने भी अग्निवीर बनने की इच्छा जताई। देश के हर हिस्से में इसको लेकर युवतियों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बिहार के लखीसराय में ऐसी ही महिला अग्निवीर अभ्यर्थियों से मिले। इस दौरान श्री राय ने अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया।

26 जून को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना युवाओं को रोजगार देने के साथ ही भारतीय सेना के माध्यम से उन्हें देशसेवा का भी गौरवपूर्ण अवसर दे रही है। सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नौकरी व रोजगार देने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। अग्निपथ योजना भी उसी का एक हिस्सा है। हाल के दिनों में इस योजनाओं को लेकर युवक-युवतियों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अग्निवीर के लिए एक तरफ आरक्षण का प्रावधान किया है, तो दूसरी ओर रोजगार मुहैया करने के लिए कई तरह की छूट भी देंगे।

9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में स्थानीय लोगों के साथ योग किया। योग करने के बाद अपने संबोधन में श्री अजय मिश्रा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योगाभ्यास किया, तो दुनिया ने भारत की संस्कृति की ताकत को देखा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 2014 को यह घोषणा की गई कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ योग के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का भागीरथी प्रयास सफल हुआ। योग जीरो प्रीमियम पर फुल हेल्थ इंश्योरेंस है। हमें अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से मानवता की सेवा के लिए लगाने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है।

इससे पहले 19 जून को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा ने गोरखपुर में गीता प्रेस कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देने की घोषणा हो चुकी थी। श्री अजय मिश्रा ने कहा कि बीते दशकों में भारतीय जनमानस को सनातन संस्कृति से जिस प्रकार गीता प्रेस ने पुस्तकों के माध्यम से जानकारी दी है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने गीता प्रेस से जुड़े कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि गीता प्रेस ने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले कई दशकों से सराहनीय सहयोग किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का नाम दुनिया के हर देश में विशेष आदर से लिया जा रहा है। भारतीयों के प्रति दूसरे देश के नागरिकों में सम्मान का भाव पहले से अधिक आया है। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। वहां भारतवंशियों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलना बेहद आह्लादकारी अनुभव रहा। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान तक, वे एकता और विविधता का प्रतीक हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तियों से जुड़ने का अवसर पाकर प्रेरित और आभारी महसूस कर रहा हूं। बीते नौ वर्षों में पूरी दुनिया में भारत का नाम और तेजी से बढ़ा है। ■

सुरक्षा और विकास पर जोर

20 जून को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला से भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री मिलिंदा मोरागोडा ने मुलाकात की।

» ब्यूरो

तकनीक के बढ़ते उपयोग में कई प्रकार की नई चुनौतियां भी आई हैं। ऐसा ही एक नॉन-फंगीबल टोकन एनएफटी है। यह एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है। एनएफटी के युग में अपराध और साइबर सुरक्षा पर जी-20 के कार्यसमूह की बैठक निर्धारित है। इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं और उपायों/कदमों की समीक्षा के लिए 14 जून, 2023 को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एनएफटी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मेटावर्स में जी-20 के सदस्य देशों, नौ आमंत्रित देशों के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। गृह मंत्रालय के पास साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग है, जो साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध से केंद्रित तरीके से निपटता है।

भारत का सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड बांग्ला देश (बीजीबी) की 11 से 14 जून तक दिल्ली के छावला कैंप में 53वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी दौरान 13 जून को बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल एकेएम नजमुल हसन ने भारत के केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों के बीच सम्मेलन के नतीजे पर संतोष व्यक्त किया गया। भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। कहा गया कि विश्वास निर्माण उपायों के रूप में किए गए सहमत कार्यक्रमों के माध्यम से आपसी सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, बीएसएफ और बीजीबी के बीच आपसी सहयोग ने त्रिपुरा में सिंगल रोड के निर्माण और विकास कार्यों को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। पड़ोसी देशों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर से लगातार बेहतर प्रयास किए जाते हैं। 20 जून को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला से भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त श्री मिलिंदा मोरागोडा ने मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंकाई पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ सहयोग और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री मिलिंदा मोरागोडा की ओर से भी कहा गया कि भारत के केंद्रीय गृह सचिव के साथ उनकी मुलाकात बेहद सार्थक रही और दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा की।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) को सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान और 800 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान का निर्माण पूरा होने वाला है और परियोजना को जल्द से जल्द चालू करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और NIT। के परामर्श से केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 14 जून को एम्स, नई दिल्ली के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। आयोग, सीएपीएफआईएमएस और एम्स, नई दिल्ली के बीच निष्पादित किए जाने वाले ट्राइट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करेगा।

केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने 20 जून, 2023 को नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी की कार्यकारी परिषद की 62वीं बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकारी परिषद ने गतिविधियों की समीक्षा की और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट को मंजूरी दी। ■

श्री अशोक प्रसाद*

जम्मू और कश्मीर

शांति, प्रगति और विकास के नए युग का आरंभ

एक समय था जब जम्मू-कश्मीर के विकास पर लंबा स्पीड ब्रेकर था। इतना भयावह माहौल था कि छुटपुट विकास भी दिखता नहीं था। आज निर्भय होकर और डंके की चोट पर कह सकते हैं कि वे दिन गए जब जम्मू और कश्मीर को अवसर विद्रोह, आतंकवाद, अलगाववादी विरोध प्रदर्शन और सीमा पार घुसपैठ की घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस काले सप्ताह माहौल के परिणामस्वरूप क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल पसरा हुआ था। भारत सरकार का तहेदिल से धन्यवाद जिनके अग्रणी कदमों की बदौलत कश्मीर का हर नागरिक खुली हवा में बेखौफ सांस ले सकता है, कश्मीर की सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। यह सब कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

आज डंके की चोट पर कह सकते हैं कि कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में शांति और प्रगति के एक नए युग को अपनाया है। लोगों के बीच सुरक्षा और शांति का माहौल स्थापित करना जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण था, जहां पिछले कुछ दशकों में उग्रवाद और हिंसा की घटनाएं बार-बार देखी गई थीं। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन आतंकी घटनाओं के कारण निर्दोष लोगों की जानें चली गई थीं। इसके अलावा अशांति और अस्थिरता की लंबी अवधि ने विकास के पथ को बाधित कर दिया था। परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना खराब हो गया था। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए बहुआयामी नीतिगत उपायों को शामिल करते हुए एक एकीकृत कार्य योजना बनाई। जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास में अनुच्छेद 370 स्पीड ब्रेकर था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इसे निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 31 अक्टूबर, 2019 के बाद, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिए गये।

भारत सरकार का जम्मू-कश्मीर में एक और उल्लेखनीय कदम है, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस उल्लेखनीय कदम के तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज को जमीनी स्तर पर लाकर लोकतंत्र को बढ़ावा देकर इसे मजबूती प्रदान की। यहां सात वर्षों के बाद 2018 में 33,592 पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों वाली 4,290 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए। इसी तरह यहां विकास परिषदों के चुनाव हुए। ऐसा 13 साल के अंतराल के बाद हुआ। नवंबर और दिसंबर 2018 के बीच शहरी स्थानीय निकायों के 1,145 वार्डों में चुनाव हुए और अक्टूबर 2019 में जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार ब्लॉक विकास परिषदों में चुनाव हुए। ये सभी ऐतिहासिक पहल न्याय के एक नए युग की शुरूआत कर रही हैं, इस क्षेत्र को मुख्यधारा में ला रही हैं तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बराबर ला रही हैं। इसने नौकरियों के अवसरों को बढ़ाया है और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिया है।

> आज डंके की चोट पर कह सकते हैं कि कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में शांति और प्रगति के एक नए युग को अपनाया है। लोगों के बीच सुरक्षा और शांति का माहौल स्थापित करना जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण था, जहां पिछले कुछ दशकों में उग्रवाद और हिंसा की घटनाएं बार-बार देखी गई थीं। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन काली घटनाओं के कारण निर्दोष नागरिकों की जानें चली गई थीं। इसके अलावा अशांति और अस्थिरता की लंबी अवधि ने विकास के पथ को बाधित कर दिया था। परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना खराब हो गया था।

शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आदि जैसे कानूनों सहित सभी केंद्रीय कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश पर पूरी तरह से लागू किया गया। इन कानूनों का कार्यान्वयन एससी, एसटी, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी के लिए समानता और निष्पक्षता की गारंटी देता है। यहां हमेशा शांति और समृद्धि रहे, इसके लिए कानून और व्यवस्था स्थापित करना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की एकीकृत कार्य योजना के समर्थन से सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित अर्धसैनिक बल पुलिस प्रणाली के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिसकी बानगी देते हैं यहां आतंकवादी नेटवर्क उग्रवाद का खत्म होना।

इस बाबत आंकड़ों की बात करें तो पिछले नौ वर्षों में क्षेत्र में आतंकी घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2018 में 228 से घटकर 2022 में 125 हो गई है, सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या 2018 में 91 से घटकर 2022 में 31 हो गई है। जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जिसमें शामिल हैं- औद्योगिक नीति, औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति, ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति, नई फिल्म नीति और पर्यटन के लिए होम स्टे और हाउस बोट नीति।

पिछले कुछ वर्षों में इन सतत नीतिगत उपायों ने निवेशकों और पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ निवेश का दायरा भी बढ़ रहा है। 2022 में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए। पहले इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब इस ओर स्थितियां बदली हैं। बेहिचक कह सकते हैं कि निरंतर प्रशासनिक प्रयासों से रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने युवाओं को 28,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, 51,000 स्वरोजगार इकाइयां स्थापित की हैं, मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका प्रदान की है और पूरी पारदर्शिता के साथ 28,400 करोड़ का औद्योगिक पैकेज आवंटित किया है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जम्मू-कश्मीर निरंतर विकास की राह पर चल पड़ा है और वह दिन दूर नहीं जब इसे देश के सबसे विकसित और शांतिपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाएगा।■

*पूर्व पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर और विशेष निदेशक, आईबी

20 जून को गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरईडीएआई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने 13 जून को जयपुर में आयोजित रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में भर्ती हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 198 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने अभ्यर्थियों को सदाचार एवं ईमानदारी से नौकरी करते हुए अपने संस्थान एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी करने हेतु प्रेरित किया।

नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21वीं बटालियन आईटीबीपी, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बटालियन द्वारा विभिन्न स्थानों पर योग सत्र का आयोजन किया गया। इसके साथ पूरे देश में आईटीबीपी के जवानों ने अपने कार्यस्थलों पर योग किया।

तिहाड़ जेल में उन्नति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अपर महानिदेशक श्रीमती अनुपमा एन चंद्रा की उपस्थिति में दिल्ली जेल और उस्मानिया विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ. वीना पिंतालापुरी, प्रोफेसर पी लक्ष्मीनारायण, रजिस्ट्रार, तिहाड़ जेल के पुलिस महानिरीक्षक श्री एचपीएस सरन उपस्थित थे।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यून पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विभा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

"अब जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी और पड़ोसी देश के आह्वान पर बंद की घटनाएँ विलुप्त होती जा रही हैं और आतंकी घटनाओं पर बहुत नियंत्रण आया है। आज यहां स्कूल, कॉलेज, उद्योग चल रहे हैं, 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक 2022 में जम्मू और कश्मीर में आए, जो आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।"

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग- 48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India https://bprd.nic.in